वेद प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा

चंडीगढ़ उच्च न्यायालय (जस्टिस टी. पी. एस.मान,)

समक्ष निर्मल यादव और टी. पी. एस. मान माननीय न्यायमूर्ति

वेद प्रकाश और अन्य-याचिकाकर्ता
बनाम
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ और अन्य,-उत्तरदाता

C.W.P.No. 10395/2006

26 फरवरी, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997-नियम। 7-अधीनस्थ न्यायालयों में कनिष्ठों को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत करना-इसे चुनौती देना-अधीक्षक के पद को नियम के तहत दिए गए चयन द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा भरा जाएगा। 7 (i) जो यह उपबंध करता है कि विधि स्नातकों को वरीयता दी जाएगी-याचिकाकर्ता 3 से 6 जिनके पास विधि स्नातक की अर्हता है-याचिकाकर्ताओं का सेवा रिकॉर्ड जो कि उत्तरदाता 2 से 9 तक नहीं है-उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद चयन-अधीक्षकों के रूप में उत्तरदाताओं के चयन के आदेशों को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया-याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि जिला और सत्र न्यायाधीशों के कार्यालयों में अधीक्षकों के कार्य की प्रकृति के लिए दिन-रात कानून से निपटने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में, उन पात्र लोगों की सेवाएं होना फायदेमंद होगा, जो कानून स्नातक थे। नियम 7 (i) स्पष्ट रूप से अधीक्षक ग्रेड I के पद के लिए अपना चयन करने वाले उम्मीदवार की अपेक्षित आवश्यकता के अनुरूप है। हालांकि, साथ ही यह माना जाना चाहिए कि वरीयता केवल तभी लागू होगी जब उपयुक्त उम्मीदवारों के बीच अन्य सभी चीजें गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समान हों।
(Para 14)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक ओर याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करते हुए और उत्तरदाता नं। दूसरी ओर 2 से 9 तक, विशेष रूप से विधि में स्नातक की अधिमान्य योग्यता के संबंध में, यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता सं. 1 और 2, बाकी सभी कानून स्नातक हैं हालांकि, याचिकाकर्ताओं के सेवा रिकॉर्ड के रूप में नं। 3 से 6 तक निशान तक नहीं पाया गया है और इसलिए याचिकाकर्ता नं। 1 और 2 विज़-ए-विज़ उत्तरदाता नं। 2 से 9 तक, उन्हें अधीक्षक ग्रेड I के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। इस प्रकार, आक्षेपित कार्यालय आदेश को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है जिसमें उत्तरदाता नं। 2 से 9 को जिला कार्यालय में अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और उसके बाद अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति के लिए, सहायक के पद पर कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए और पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत द्वारा शासित होती है। दूसरी शाखा में स्टेनो-टाइपिस्ट शामिल हैं, जिन्हें आशुलिपिक/निर्णय लेखक (जूनियर ग्रेड) के पद पर और फिर निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नत किया जाता है (Senior Grade). जजमेंट राइटर (सीनियर ग्रेड) के पद पर पदोन्नति के लिए आशुलिपिक/जजमेंट राइटर (जूनियर ग्रेड) के पद पर कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए और ऐसी पदोन्नति फिर से वरिष्ठता-सह-योग्यता पर आधारित होती है। नियम 7 (i) ने अधीक्षक के पद पर नियुक्ति का तरीका और योग्यता प्रदान की। इस पद को उच्च न्यायालय द्वारा स्नातक अधीक्षक ग्रेड-II, निर्णय लेखक (वरिष्ठ ग्रेड) सहायक, निर्णय लेखक (जूनियर ग्रेड) और आशुलिपिक के बीच चयन द्वारा भरा जाना है, जिनकी आयु 40 वर्ष से कम नहीं थी।

(3) परिपत्र/पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2006 के माध्यम से प्रत्यर्थी नं. 1 हरियाणा राज्य में जिला और सत्र न्यायाधीशों के कार्यालयों में अधीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए चयन-सूची तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं नं। 2 से 9 ने निर्धारित समय के भीतर अपने-अपने आवेदन जमा किए। हालाँकि, याचिकाकर्ता चयन के उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक औपचारिक संचार की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन न तो उन्हें कोई सूचना मिली और न ही चयन मानदंड बताए गए। अंततः, प्रतिवादी नं द्वारा आक्षेपित कार्यालय आदेश was.issuted। 1 7 जुलाई, 2006 को, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तरदाता नं. 2 से 9 का चयन किया गया है और परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य में जिला और सत्र न्यायाधीशों के संबंधित कार्यालयों में अधीक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति/नियुक्ति के लिए पत्र/आदेश जारी किए गए थे। यह दलील देते हुए कि उत्तरदाताओं का चयन नं. 2 से 9 को नियम 7 (i) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया था और याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया था, याचिकाकर्ताओं ने विवादित कार्यालय आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

(4) अपने लिखित कथन में, प्रत्यर्थी नं। 1 ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और चूंकि उन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, इसलिए उन्हें हरियाणा राज्य में विधि और सत्र न्यायाधीशों में रखा गया है।

(Paras 17 & 18)

याचिकाकर्ताओं के वकील डॉ. सूर्य प्रकाश।

डॉ. बलराम गुप्ता, पंकज शर्मा और राजेश्वर सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 1.

पंकज कटिया, संजीव बंसल के वकील, प्रतिवादियों के वकील नं। 2,3,5,6,8 और 9.

सोम दत्त शर्मा, प्रतिवादी नं. 4.

राज मोहन सिंह, प्रतिवादी नं. 7.

टी. पी. एस. मान माननीय न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता 7 जुलाई, 2006 को प्रत्यर्थी सं. 1, जिसके द्वारा उत्तरदाता नं। 2 से 9 तक, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार उनसे कनिष्ठ थे, उन्हें हरियाणा के अधीनस्थ न्यायिक न्यायालयों में अधीक्षक (ग्रेड-I) के पद पर पदोन्नत किया गया था और यह भी कि उत्तरदाता नं। 2 से 9 हरियाणा अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997 के नियम 7 का उल्लंघन करते हुए बनाया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र की एक रिट जारी करने की मांग की।

(2) रिट याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि हरियाणा में अधीनस्थ न्यायालयों में मंत्री कर्मचारियों की सेवा शर्तें हरियाणा अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित हैं, जिसके अनुसार मंत्री कर्मचारियों को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहली शाखा में, प्रारंभिक नियुक्तियां क्लर्क के पद पर की जाती हैं, जिन्हें बाद में सहायक के पद पर और उसके बाद अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में पदोन्नत किया जाता है। इसके अलावा, अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति के लिए, सहायक के पद पर कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए और पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत द्वारा शासित होती है। दूसरी शाखा में स्टेनो-टाइपिस्ट शामिल हैं, जिन्हें आशुलिपिक/निर्णय लेखक (जूनियर ग्रेड) के पद पर और फिर निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नत किया जाता है (Senior Grade). जजमेंट राइटर (सीनियर ग्रेड) के पद पर पदोन्नति के लिए आशुलिपिक/जजमेंट राइटर (जूनियर ग्रेड) के पद पर कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए और ऐसी पदोन्नति फिर से वरिष्ठता-सह-योग्यता पर आधारित होती है। नियम 7 (i) ने अधीक्षक के पद पर नियुक्ति का तरीका और योग्यता प्रदान की। इस पद को उच्च न्यायालय द्वारा स्नातक अधीक्षक ग्रेड-II, निर्णय लेखक (वरिष्ठ ग्रेड) सहायक, निर्णय लेखक (जूनियर ग्रेड) और आशुलिपिक के बीच चयन द्वारा भरा जाना है, जिनकी आयु 40 वर्ष से कम नहीं थी।

(3) 17 फरवरी, 2006 के परिपत्र/पत्र के माध्यम से प्रतिवादी नं। 1 हरियाणा राज्य में जिला और सत्र न्यायाधीशों के कार्यालयों में अधीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए चयन-सूची तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं नं। 2 से 9 ने निर्धारित समय के भीतर अपने-अपने आवेदन जमा किए। हालाँकि, याचिकाकर्ता चयन के उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक औपचारिक संचार की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन न तो उन्हें कोई सूचना मिली और न ही चयन मानदंड बताए गए। अंततः, प्रतिवादी नं द्वारा आक्षेपित कार्यालय आदेश was.issuted। 1 7 जुलाई, 2006 को, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तरदाता नं. 2 से 9 का चयन किया गया है और परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य में जिला और सत्र न्यायाधीशों के संबंधित कार्यालयों में अधीक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति/नियुक्ति के लिए पत्र/आदेश जारी किए गए थे। यह दलील देते हुए कि उत्तरदाताओं का चयन नं. 2 से 9 को नियम 7 (i) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया था और याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया था, याचिकाकर्ताओं ने विवादित कार्यालय आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

(4) अपने लिखित कथन में, प्रत्यर्थी नं। 1 ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और चूंकि उन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, इसलिए उन्हें प्रतिवादी नं। 2 से 9 तक। यह भी कहा गया था कि-हरियाणा राज्य द्वारा 9 मई, 1985 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, केवल ऐसे अधिकारी या अधिकारी, जिन्होंने पिछले दस वर्षों के दौरान "अच्छी" या बेहतर श्रेणियों की कम से कम 70% या अधिक रिपोर्ट प्राप्त की थी, उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र माना जा सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने हरियाणा में अधीनस्थ न्यायालयों में मंत्री कर्मचारियों में पदोन्नति के लिए अपने स्वयं के नियम बनाए थे। इसलिए, सेवा की शर्तें उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा शासित थीं, जबकि हरियाणा राज्य द्वारा जारी निर्देशों को अपनाया नहीं गया था। अन्यथा भी, हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देश केवल पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए लागू थे, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में अधीक्षकों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार चयन के माध्यम से होती है। अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवेदन हरियाणा राज्य में संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीशों के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। आवेदन प्राप्त होने के बाद, मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत गठित माननीय न्यायाधीशों की समिति के समक्ष रखा गया। उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, समिति ने उन्हें चयन-सूची में लाने के लिए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की और उन नामों को 25 मई, 2006 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में माननीय न्यायाधीशों द्वारा अनुमोदित किया गया। तदनुसार, चयन-सूची तैयार की गई और उसी से नियुक्तियां की गईं। इस बात से इनकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं को कोई भी संचार, जो भी हो, भेजा जाना था। सभी पात्र व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के साथ-साथ सेवा रिकॉर्ड के आधार पर,

आवेदन करने वाले 62 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी। सूची में सेवा में प्रवेश की तारीख, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/शिकायतों की योग्यता और सटीक विवरण शामिल थे।

4,537/5,000 Characters

Translate

पहली सूची के बाद, उम्मीदवारों की एक और सूची, जिनके पास LL.B की योग्यता थी। तैयार था। उपर्युक्त अभ्यास के बाद, दोनों सूचियों को, सभी उम्मीदवारों के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड के साथ, माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित माननीय न्यायाधीशों की समिति के समक्ष रखा गया था। समिति ने नियमों में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की भी जांच की। उनके रिकॉर्ड के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उत्तरदाता नं। जिला अनु सत्र न्यायाधीशों के अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता के क्रम में 2 से 9 की सिफारिश की गई थी। अधीक्षकों के आगे के पदों के बारे में तथ्य से अवगत होने के कारण, जो निकट भविष्य में खाली होने की संभावना थी, समिति ने अगले दो वर्षों के भीतर अवशोषण के लिए चयन-सूची में तीन और उम्मीदवारों को भी रखा। चूंकि याचिकाकर्ता चयनित उम्मीदवारों की तुलना में कम मेधावी और कम योग्य थे, इसलिए उन्हें उत्तरदाता नं। 2 से 9 तक। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(5) निजी उत्तरदाताओं ने भी अपने लिखित बयान दायर किए और कहा कि उन्हें नियमों के अनुसार अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

(6) हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और याचिकाकर्ताओं के सेवा रिकॉर्ड को भी देखा है, इसके अलावा उत्तरदाता नं। 2 से 9 तक।

(7) आगे बढ़ने से पहले, नीचे दिए गए नियम 7 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा, जो अधीक्षक, निर्णय लेखक (वरिष्ठ ग्रेड) अधीक्षक (ग्रेड-II) निर्णय लेखक (जूनियर ग्रेड)/आशुलिपिक, सहायक, स्टेनो-टाइपिस्ट और क्लर्क के पदों पर नियुक्ति और योग्यता के तरीके से संबंधित हैः- "7. पदों पर नियुक्ति का तरीका और योग्यताः

(i) अधीक्षक

जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक का पद राज्य संवर्ग में होगा और उच्च न्यायालय द्वारा स्नातक अधीक्षक ग्रेड-II, निर्णय लेखक (वरिष्ठ ग्रेड) सहायक, निर्णय लेखक (कनिष्ठ ग्रेड) और आशुलिपिकों में से चयन करके भरा जाएगा, जिनकी आयु उस तारीख को 40 वर्ष से कम नहीं है जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तथापि, विधि स्नातकों को वरीयता दी जाएगीः बशर्ते कि संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश छुट्टी की रिक्ति में या अन्यथा तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए या उच्च न्यायालय द्वारा नियमित नियुक्ति किए जाने तक उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा पुष्टि के अधीन अधीक्षक के पद पर कार्यवाहक नियुक्ति कर सकता है।

जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की एक चयनित सूची उच्च न्यायालय द्वारा तैयार/बनाए रखी जाएगी। इस सूची में केवल उतने ही उम्मीदवार होंगे जिन्हें दो साल के भीतर शामिल किया जा सकता है।

किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में स्वीकृति के लिए विचार करने से पहले वह एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा कि यदि वह इस रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह हरियाणा राज्य में कहीं भी तैनात होने के लिए तैयार होगा और स्थानांतरण के विरोध की स्थिति में वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

वर्ग III

(ii) निर्णय लेखक (Senior Grade)

जजमेंट राइटर (सीनियर ग्रेड) की नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर तीन साल के अनुभव के साथ आशुलिपिक/जजमेंट राइटर (जूनियर ग्रेड) में से पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

(iii) अधीक्षक ग्रेड-II

अधीक्षक ग्रेड-II की नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर तीन साल के अनुभव वाले सहायकों में से पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

(iv) निर्णय लेखक (जूनियर ग्रेड)/आशुलिपिक

जजमेंट राइटर (जूनियर ग्रेड)/आशुलिपिक की नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर तीन साल के अनुभव के साथ आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

(v) सहायक

सहायक की नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले पहले से ही सेवा में (इन नियमों के लागू होने से पहले) स्नातक क्लर्कों में से पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

(vi) स्टेनो-टाइपिस्ट

स्टेनो-टाइपिस्ट के पद पर नियुक्ति सीधे भर्ती द्वारा की जाएगी; ऐसे उम्मीदवार जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या समकक्ष की डिग्री है और 80 W.P.M की गति से एक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। अंग्रेजी शॉर्टहैंड और 20 W.P.M. उसी के प्रतिलेखन में। योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची परिणाम की घोषणा की तारीख से एक वर्ष के लिए लागू रहेगी।

(vii) क्लर्क

क्लर्क के पद पर नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में 90% और पदोन्नति के माध्यम से 10% के अनुपात में की जाएगी।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX "

(8) जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, अधीक्षक के पद को स्नातक अधीक्षक ग्रेड-II, निर्णय लेखक (वरिष्ठ ग्रेड) सहायक, निर्णय लेखक (जूनियर ग्रेड) और आशुलिपिकों के बीच से भरा जाना आवश्यक है, जिनकी आयु 40 वर्ष से कम नहीं है। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वरीयता विधि स्नातकों को दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी पद को धारण कर सकता है, i.e., अधीक्षक ग्रेड-II, जजमेंट राइटर (वरिष्ठ ग्रेड) सहायक, जजमेंट राइटर (जूनियर गद्रे) और आशुलिपिक का चयन अधीक्षक ग्रेड-I के पद के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, उसे उक्त उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा चुना जाना है।

(9) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा एक तर्क दिया गया था कि जबकि एक सहायक को अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, उसके पास अधीक्षक के रूप में पदोन्नत होने के लिए तीन साल का अनुभव होने के बाद ही, हो सकता है कि उसे कोई अनुभव न हो। अधीक्षक ग्रेड-II, जजमेंट राइट (सीनियर ग्रेड) जजमेंट राइटर (जूनियर ग्रेड)/आशुलिपिक और सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए इसी तरह की आवश्यकता निर्धारित की गई है। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि जहां भी तीन साल के अनुभव की आवश्यकता निर्धारित की गई है, वह केवल उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से थी, न कि चयन के लिए। अधीक्षक का पद, जैसा कि नियमों से स्पष्ट है, केवल एक चयन पद है न कि पदोन्नति पद। अधीक्षक के रूप में चयनित होने के लिए, पात्र उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों की जांच माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए गठित माननीय न्यायाधीशों की समिति द्वारा की जानी आवश्यक है। इसलिए, हमें नियम 7 के प्रावधानों में कोई विसंगति नहीं मिलती है, जहां तक वे अधीक्षक के पद पर नियुक्ति और अन्य पदों पर पदोन्नति से संबंधित हैं, i.e. अधीक्षक ग्रेड-II, जजमेंट राइटर (सीनियर ग्रेड) जजमेंट राइटर (जूनियर ग्रेड)/आशुलिपिक और सहायक।

(10) अधीक्षक के पद के लिए चयन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि विधि स्नातकों को वरीयता दी जाएगी। अब यह देखा जाना चाहिए कि क्या इसका अर्थ योग्यता और उपयुक्तता के बावजूद विधि स्नातकों को वरीयता देना है या वरीयता को केवल एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में माना जाना है, अन्य चीजें गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समान हैं।

(11) A.P. की सरकार बनाम पी. दिलीप कुमार[1] माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रशासनिक निष्पादन में सुधार प्राप्त करने की दृष्टि से उच्च शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के लिए घृणित नहीं था। न्यायालय को उस मामले का संज्ञान लिया गया था जिसमें योग्यता परीक्षा में सफल नहीं होने वाले उम्मीदवारों को हटाकर विचार क्षेत्र को संकुचित कर दिया गया था और उन उम्मीदवारों में से, जो योग्यता परीक्षा में सफल हुए और साक्षात्कार के बाद

---

[1] (1993) 2 SCC 310

न्यूनतम परीक्षा अंक प्राप्त किए, पर विचार किया गया था और उसके बाद प्रक्रिया चयन में, वरीयता नियम पहले स्नातकोत्तर और उसके बाद स्नातक का चयन करके लागू किया गया था।

(12) सचिव, A.P. लोक सेवा आयोग बनाम YV.V.R. श्रीनिवासुलु और अन्य[2] माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अतिरिक्त योग्यता को वरीयता देने का अर्थ होगा कि अन्य चीजें गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समान होने के कारण, अतिरिक्त योग्यता रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह अंतर योग्यता और उपयुक्तता के बावजूद एन ब्लॉक वरीयता का संकेत नहीं देता था और अतिरिक्त योग्यता आरक्षण या पूर्ण प्राथमिकता के रूप में काम नहीं कर सकती थी। हालांकि, उक्त मामले में, पुराने नियम, जिनके आधार पर वरीयता का दावा किया गया था, को हटा दिया गया और नए नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसने वरीयता प्रावधान को हटा दिया। इसके अलावा, पुराने नियमों के तहत भी, वरीयता दी जानी थी, पहले उन उम्मीदवारों को, जिनके पास वाणिज्य में डिग्री और कानून में डिग्री थी, दूसरा उन उम्मीदवारों को, जिनके पास वाणिज्य में डिग्री थी और तीसरा उन लोगों को, जिनके पास कानून में डिग्री थी और इसलिए, 'प्रथम' शब्द का अर्थ केवल उसमें इंगित क्रम और तरीके से वरीयता देने के संदर्भ में लगाया जाना था, जो कि डिग्री के इस तरह के अंतर वर्ग को रखने वाले एक से अधिक लोगों के बीच था और दूसरों की तुलना में व्याख्या नहीं की जानी थी, जिनके पास ऐसी अतिरिक्त योग्यता नहीं थी ताकि उन्हें समूह में बाहर किया जा सके। न्यायालय ने बिभूदत्त मोहंती बनाम भारत संघ[3] और सचिव मामले में निर्णय पर भरोसा किया। (स्वास्थ्य) विभाग। स्वास्थ्य और F.W. बनाम डॉ. अनीता पुरी[4]. हालाँकि, न्यायालय ने पी. दिलीप कुमार के मामले (उपर्युक्त) में लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके अनुसार, उस निर्णय ने न केवल विचाराधीन सेवा नियमों की विशिष्ट योजना और संदर्भ को प्रभावित किया, बल्कि सभी मामलों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सामान्य नियम निर्धारित करने की भी घोषणा नहीं की।

(13) U.P. राज्य में। और एक अन्य बनाम ओम प्रकाश और अन्य[5] माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से अभिनिर्धारित किया कि जब चयन प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से मूल्यांकन की गई योग्यता के आधार पर किया जाता है, तो अतिरिक्त योग्यता को वरीयता देने का अर्थ होगा कि अन्य झुकाव गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समान हैं, जिनके पास अतिरिक्त योग्यता है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वरीयता का मतलब अंतर योग्यता और उपयुक्तता के बावजूद एन ब्लॉक वरीयता नहीं था।

(14) वर्तमान मामले में, हम जिला और सत्र न्यायाधीशों के कार्यालयों में अधीक्षकों के पदों पर नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं। उनके काम की प्रकृति के लिए दिन-रात कानून से निपटने की आवश्यकता होगी।

---

2 (2003) 5 SCC 341
3 2002 (4) SCC 16
4 (1996) 6 SCC 282
5 (2006) 6 SCC 474

ऐसी स्थिति में, उन पात्र लोगों की सेवाएं होना फायदेमंद होगा, जो कानून स्नातक थे। नियम 7 (i) स्पष्ट रूप से अधीक्षक ग्रेड-I के पद के लिए अपना चयन करने वाले उम्मीदवार की अपेक्षित आवश्यकता के अनुरूप है। हालांकि, साथ ही यह माना जाना चाहिए कि वरीयता केवल तभी लागू होगी जब उपयुक्त उम्मीदवारों के बीच अन्य सभी चीजें गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समान हों।

(15) प्रत्यर्थी नं. 1 ने एक चार्ट प्रस्तुत किया था जिसमें याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं की योग्यता के अलावा उनके सेवा रिकॉर्ड और अनुभव का विवरण दिया गया था। उसी के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता नं। 1 का पिछले पाँच वर्षों में उत्कृष्ट रिकॉर्ड था, लेकिन प्रतिलिपि की आपूर्ति के लिए आवेदन को रोकने से संबंधित शिकायत के संबंध में एक चेतावनी दी गई थी। याचिकाकर्ता के मामले में नं. 2, हालांकि कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है, फिर भी छद्म शिकायतों के आधार पर, उसके खिलाफ विस्तृत पूछताछ की जा रही थी। याचिकाकर्ता नं. पर 'सेंसर' का जुर्माना लगाया गया था। 3 9 फरवरी, 1993 को, जबकि वर्ष 1998 के लिए उनके काम और आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की गईं, जिन्हें बता दिया गया था। वर्ष 2001 के लिए प्रतिकूल टिप्पणियां ("औसत") याचिकाकर्ता नं. 4. संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा 17 अक्टूबर, 2002 को पारित आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 24 जुलाई, 2001 से 31 अगस्त, 2001,3 दिसंबर, 2001 से 20 दिसंबर, 2001 और 22 दिसंबर, 2001 से 21 अप्रैल, 2002 तक जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित माना गया था। याचिकाकर्ता के मामले में नं। 5, उन्हें दुर्व्यवहार के लिए निंदा की गई थी-संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 21 दिसंबर, 2006 के आदेश के अनुसार। एक लाख रुपये का जुर्माना। 10 उन पर 23 सितंबर, 1980 को एक भी मामले की फाइल नहीं भेजने के लिए लगाया गया था। 22 जुलाई, 1988 को गंभीर चूक के लिए एक महीने के वेतन का जुर्माना लगाया गया था, जिसे बाद में चेतावनी के साथ बदल दिया गया था। याचिकाकर्ता नं. उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 400 8 सितंबर, 1998 को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के कारण। इससे पहले भी 3 दिसंबर, 1993 को, वह ड्यूटी से अनुपस्थित पाई गई थी और वह जिला और सत्र न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति-कक्ष के अंदर गई थी और उस समय उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी जब अधिकारी अदालत में थे। प्रतिवादी सं. द्वारा निर्दिष्ट याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त पृष्ठभूमि में। 1 प्रदान किए गए चार्ट में, हमारे विचार से उन्हें अधीक्षक ग्रेड-I के रूप में तैनात होने के लिए उचित रूप से नहीं चुना गया था।

(16) याचिकाकर्ताओं के अनुबंध में, निजी उत्तरदाताओं के पास उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड है। उत्तरदाताओं के संबंध में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं है नं। 2. 3, 4. 6 और 8. तथापि, यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी सं. 16 फरवरी, 1995 को संचयी प्रभाव के बिना 5 को रोक दिया गया था और उन्हें भविष्य में आधिकारिक रिकॉर्ड से निपटने में बहुत सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था और संचयी प्रभाव के बिना एक वृद्धि को रोकने को चेतावनी में बदल दिया गया था। प्रत्यर्थी के मामले में नं. 7, उन्हें 29 जनवरी, 1976 को संबंधित जिला और सत्र

न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी से अवगत कराया गया था कि उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में एक मौखिक शिकायत प्राप्त हुई थी और उन्हें तदनुसार चेतावनी दी गई थी, जबकि प्रतिवादी नं. 9 को 7 दिसंबर, 2002 को ऑडिट के समय ऑडिट पार्टी को रिकॉर्ड नहीं दिखाने के लिए चेतावनी का दंड लगाया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निजी उत्तरदाताओं में से पांच का बेदाग सेवा रिकॉर्ड है, जबकि शेष निजी उत्तरदाताओं को केवल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण पाया गया, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि वे अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं थे।

(17) एक ओर याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करते हुए और उत्तरदाता नं। दूसरी ओर 2 से 9 तक, विशेष रूप से विधि में स्नातक की अधिमान्य योग्यता के संबंध में, यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता सं. 1 और 2, बाकी सभी कानून स्नातक हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के सेवा रिकॉर्ड के रूप में नं। 3 से 6 तक निशान तक नहीं पाया गया है और इसलिए याचिकाकर्ता नं। 1 और 2 विज़-ए-विज़ उत्तरदाता नं। 2 से 9 तक, उन्हें अधीक्षक ग्रेड-I के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

(18) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित कार्यालय आदेश (अनुलग्नक पी. 4) को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, जिसके तहत उत्तरदाता नं। हरियाणा राज्य में जिला और सत्र न्यायाधीशों के कार्यालयों में अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए 2 से 9 का चयन किया गया है।

(19) वर्तमान रिट याचिका बिना किसी योग्यता के है और इसलिए खारिज कर दी गई है।

(20) फैसला देने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता इस बार अपनी योग्यता के कारण ऐसा नहीं कर सके, जो उत्तरदाता सं. 2 से 9 तक। हालाँकि, उन्हें भविष्य में अधीक्षक ग्रेड-I के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा, यदि वे मानदंडों को पूरा करते हैं और योग्यता के आधार पर उच्च रैंक पर रखे जाते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा